अब बिजनेस हब बनकर चमकेगा बुंदेलखंड

जितेन्द्र शुक्ल • कानपुर

- बुंदेलखंड विकास निधि के लिए मिले 425 करोड़ रुपये
- किसान फसलों के हिसाब से ले सकेंगे अस्थायी कनेक्शन

<< बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने कनेक्टिविटी आसान कर दी।

योगी सरकार का फोकस बुंदेलखंड पर है, यह बात सोमवार को पेश किए गए बजट से साबित हो गई है। किसान, पर्यटन और औद्योगिक विकास सहित सबके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था की गई है। कनेक्टिविटी के रूप में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन ही चुका है, अब यहां नोएडा की तर्ज पर टाउनशिप विकसित करने की तैयारी है। कभी पिछड़ा माना जाने वाला यह क्षेत्र औद्योगिक विकास प्राधिकरण से बिजनेस हब बनेगा।

बजट में बुंदेलखंड विकास निधि के लिए 425 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यहां के लिए नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया ही जा चुका है। अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तरह औद्योगिक और आवासीय टाउनशिप भी विकसित की जाएगी। इस पर काम शुरू भी हो चुका है। बजट आवंटित होने से इसमें और रफ्तार आएगी। चित्रकूट में डिफेंस कारिडोर पहले से ही बन रहा है। देवांगना घाटी में हवाई अड्डा बनकर तैयार है और जल्द ही यहां से उड़ानें शुरू करने की भी तैयारी है। बुंदेलखंड सौर ऊर्जा का भी हब बनेगा। यहां 4000 मेगावाट के सोलर पार्क पर काम चल रहा है। जालौन में पीएसी बटालियन की स्थापना का भी रास्ता साफ हो गया है।

पानी की कमी से जूझने वाले इस क्षेत्र के डार्क जोन घोषित क्षेत्रों में ट्यूबवेल लगाने से रोक हटा दी गई है। अब किसान बिना बाधा के सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगा सकेंगे। रबी की फसल की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगाने को अस्थायी कनेक्शन लिए जा सकेंगे। यहां के लिए सीजनल टैरिफ की भी व्यवस्था की गई है। 60 वर्ष से ज्यादा आयु वाले लघु और सीमांत किसानों को पेंशन का सबसे ज्यादा फायदा बुंदेलखंड के जिलों के किसानों का होगा। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में नए कामों के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में भी नए काम हो सकेंगे।

अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनने के बाद अब प्रभु श्रीराम की तपोभूमि चित्रकूट की ओर नजर है। 2022 में श्री चित्रकूटधाम तीर्थ विकास परिषद बनने के बाद से यहां करीब 102 करोड़ की पर्यटन विकास योजनाओं पर काम चल रहा है। महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र में काम चल रहा है और इसके लिए 10.53 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल विकसित करने की योजना बनाई है।